JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

प्रतापगढ़ (राजस्थान) जिले में अनुसूचित जनजाति का राजनीतिक योगदान

(Political contribution of Scheduled Tribes in Pratapgarh (Rajasthan) district)

Author – Dr. Narayan Lal Ninama, Assistant Professor- Political Science (VSY), Government College, Arnod, Pratapgarh, Rajasthan.

Abstract : प्रतापगढ़, राजस्थान का एक जिला है जहाँ अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देता है। इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक भागीदारी का एक लंबा इतिहास रहा है, जहाँ उन्होंने न केवल वोट बैंक के रूप में बल्कि जनप्रतिनिधियों के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस जिले में, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों ने उनकी राजनीतिक आवाज़ को और मज़बूती दी है। धरियावद और प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जिसने उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया है। यह आरक्षण उन्हें राज्य और स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए काम करने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि, राजनीतिक भागीदारी के बावजूद, इस समुदाय के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास जैसी कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, समुदाय के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है। यह देखा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दल अनुसूचित जनजाति के वोटरों को लुभाने के लिए विशेष नीतियाँ और वादे करते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि इस समुदाय का राजनीतिक महत्व बढ़ रहा है। कुल मिलाकर, प्रतापगढ़ में अनुसूचित जनजाति का राजनीतिक योगदान प्रतिनिधित्व, नीति निर्माण और सामाजिक–आर्थिक विकास के प्रयासों में महत्वपूर्ण रहा है, हालाँकि अभी भी कई क्षेत्रों में प्रगति की आवश्यकता है।

Keywords : प्रतापगढ़ (राजस्थान), अनुसूचित जनजाति, राजनीतिक योगदान, धरियावद, विधानसभा, आरक्षण, प्रतिनिधि, सामाजिक–आर्थिक विकास, आदिवासी, भागीदारी, नेतृत्व, चुनाव, वोट बैंक।

Article : प्रतापगढ़ राजस्थान का सर्वाधिक जनजातीय बहुल जिला है, जहाँ विशेषकर भील जनजाति का प्रभुत्व है। भील समुदाय न केवल अपनी सांस्कृतिक अस्मिता और परंपराओं के लिए जाना जाता है, बल्कि उसने राजनीतिक चेतना और संघर्षशीलता का परिचय भी ऐतिहासिक काल से दिया है। प्रतापगढ़ क्षेत्र के भील सदियों से सामंती उत्पीड़न, भूमि से वंचित होने और सामाजिक बहिष्कार जैसी परिस्थितियों से जूझते रहे, जिसके परिणामस्वरूप उनके भीतर प्रतिरोध की चेतना विकसित हुई। इस चेतना ने उन्हें केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी सक्रिय बनाया। राजस्थान के दक्षिणी अंचल में

हुए विभिन्न जनजातीय आंदोलनों का केंद्र यही क्षेत्र रहा, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इतिहास साक्षी है कि प्रतापगढ़ और आस–पास के जनजातीय क्षेत्रों में भीलों ने औपनिवेशिक शासन और सामंती शोषण के विरुद्ध समय–समय पर विद्रोह किया। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में भीलों द्वारा चलाए गए प्रतिरोध आंदोलनों का स्वरूप भले ही बिखरा हुआ था, किंतु उनमें स्वतंत्रता और न्याय की आकांक्षा स्पष्ट दिखाई देती है। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में 'राजपूत ठिकानों' और सामंती शक्तियों के साथ मिलकर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया था, जिसके कारण भीलों पर दोहरी मार पड़ी, एक ओर अंग्रेजों का कर एवं राजस्व शोषण, दूसरी ओर स्थानीय जागीरदारों और ठिकेदारों का उत्पीड़न। इन परिस्थितियों में भीलों ने सशस्त्र प्रतिरोध किया और अपनी भूमि, सम्मान एवं जीवन जीने की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। भील आंदोलन, जिसे अक्सर 'भगत आंदोलन' के नाम से जाना जाता है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र के सामाजिक–राजनीतिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। यह आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रारंभ हुआ। भगत आंदोलन का नेतृत्व आदिवासी संतों और जागरूक व्यक्तियों ने किया, जिन्होंने भीलों को शराब, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास से दूर रहकर संगठनबद्ध होने की प्रेरणा दी। इस आंदोलन का राजनीतिक आयाम यह था कि भीलों में एकता, आत्मसम्मान और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की सामूहिक चेतना उत्पन्न हुई। इससे वे केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने लगे। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में जब राष्ट्रीय आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था, तब प्रतापगढ़ क्षेत्र के भील भी इससे अछूते नहीं रहे। महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिध्वनि यहाँ भी सुनाई दी। इस समय तक भगत आंदोलन के माध्यम से भीलों में संगठन की नींव मजबूत हो चुकी थी, जिसने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। स्थानीय नेतृत्व ने जनजातीय जनता को समझाया कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई केवल शहरी मध्यवर्ग की नहीं है, बल्कि यह उन सबकी लड़ाई है जिनका शोषण किया जा रहा है। इस विचार ने भीलों को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित किया।

स्थानीय एवं क्षेत्रीय राजनीति में भागीदारी

प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का सर्वाधिक जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जहाँ अनुसूचित जनजाति विशेषकर भील समुदाय की जनसंख्या बहुतायत में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, तब प्रतापगढ़ क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियाँ भी धीरे–धीरे स्थानीय एवं क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगीं। प्रारंभिक दौर में अशिक्षा, गरीबी और सामंती अवरोधों के कारण उनकी राजनीतिक सहभागिता सीमित रही, परंतु पंचायती राज संस्थाओं के गठन और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विस्तार ने जनजातीय समुदाय को राजनीतिक मुख्यधारा से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंचायती राज व्यवस्था के तहत गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद जैसी संस्थाओं का गठन हुआ। इन संस्थाओं ने अनुसूचित जनजातियों को पहली बार राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर दिया। प्रतापगढ़ जिले में अनुसूचित जनजातियों ने धीरे–धीरे ग्राम पंचायतों के चुनावों में हिस्सा लेना शुरू किया और अनेक ग्राम पंचायतों में सरपंच के पद पर भी निर्वाचित हुए। यह केवल स्थानीय सत्ता संरचना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पंचायत समितियों और जिला परिषद में भी जनजातीय प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रकार लोकतांत्रिक ढांचे ने उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया और स्थानीय प्रशासन में उनकी आवाज़ को स्थान दिलाया। स्थानीय राजनीति में अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसी समस्याओं को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया। उदाहरण के लिए, कई जनजातीय प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों में सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए सक्रिय प्रयास किए। पंचायत स्तर पर लिए गए इन निर्णयों ने

न केवल जनजातीय जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद की, बल्कि राजनीतिक चेतना को भी गहरा किया।

प्रतापगढ़ की अनुसूचित जनजातियाँ क्षेत्रीय राजनीति में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती रही हैं। राजस्थान में 1950 और 1960 के दशक में जब प्रजामंडल और बाद में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव था, तब जनजातीय नेता इन संगठनों के साथ जुड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। अनेक जनजातीय नेताओं ने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के मंचों पर अपनी पहचान बनाई। विधानसभा चुनावों में भी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों ने भाग लिया और प्रतापगढ़ से कई बार विधायक निर्वाचित हुए। इन नेताओं ने शिक्षा, रोजगार और वनाधिकार जैसे मुद्दों को विधानसभा में उठाकर जनजातीय समाज की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दी।

पंचायती राज में आरक्षण नीति ने अनुसूचित जनजातियों की राजनीतिक भागीदारी को और भी सुदृढ़ किया। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों ने जनजातीय महिलाओं को भी राजनीति में आने का अवसर दिया। क्षेत्रीय स्तर पर जनजातीय समुदाय ने अनेक आंदोलनों और जनसंगठनों के माध्यम से भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। वनाधिकार कानून, भूमि सुधार और शिक्षा के सवालों को लेकर उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों ने स्थानीय नेताओं को उभरने का अवसर दिया, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत हुई।

विधानसभा एवं संसदीय राजनीति में योगदान

प्रतापगढ़ जिले की अनुसूचित जनजाति, विशेषकर भील समुदाय, ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि विधानसभा और संसदीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वतंत्रता के बाद जब राजस्थान की विधानसभा और संसद में चुनावी राजनीति प्रारंभ हुई, तब अनुसूचित जनजातियों को आरक्षित सीटों के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। प्रतापगढ़ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बहुल होने के कारण यहाँ से चुने गए विधायक और सांसद प्रायः जनजातीय पृष्ठभूमि से ही रहे हैं। इन प्रतिनिधियों ने न केवल अपने समाज की समस्याओं को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय अधिकारों की आवाज़ को मजबूती से उठाया। राजस्थान विधानसभा में प्रतापगढ़ क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि सुधार और वनाधिकार जैसे मुद्दों को बार–बार उठाया। उनके प्रयासों से आदिवासी अंचलों में विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और सड़कों का जाल बिछाने की पहल हुई। साथ ही, अनुसूचित जनजातियों को वन भूमि पर अधिकार दिलाने और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने में भी उनका योगदान रहा। संसदीय राजनीति में प्रतापगढ़ से निर्वाचित सांसदों ने आदिवासी समुदाय के विकास के लिए विशेष योजनाओं, जनजातीय उपयोजना और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया। जनजातीय प्रतिनिधियों की सक्रियता ने यह सुनिश्चित किया कि प्रतापगढ़ जिले की जनजातीय समस्याएँ केवल स्थानीय मुद्दे न रहकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की नीतियों का हिस्सा बनें। इससे न केवल अनुसूचित जनजातियों की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हुई, बल्कि उनकी सामाजिक–आर्थिक प्रगति के लिए भी नए रास्ते खुले।

आधुनिक चुनौतियाँ एवं अवसर

प्रतापगढ़ जिले की अनुसूचित जनजातियाँ आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, परंतु उनके सामने कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, गरीबी, बेरोज़गारी और नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयाँ उनके राजनीतिक सशक्तिकरण में बाधक हैं। राजनीतिक दल अक्सर इन्हें केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं, जिससे वास्तविक नेतृत्व और नीतिगत सहभागिता सीमित रह जाती है। साथ ही, विकास योजनाओं का लाभ भी प्रशासनिक जटिलताओं और भ्रष्टाचार के कारण सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता। इसके बावजूद अवसर भी कम नहीं हैं। पंचायती राज

व्यवस्था, आरक्षण नीति, वनाधिकार कानून और जनजातीय उपयोजना जैसे प्रावधान अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार हैं। शिक्षा और जागरूकता के प्रसार से नई पीढ़ी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ रहा है, जिससे राजनीतिक सहभागिता का दायरा व्यापक हो रहा है। डिजिटल युग में सूचना तक पहुँच ने उन्हें अपनी समस्याओं को अधिक सशक्त रूप से उठाने का अवसर दिया है। यदि इन अवसरों का सही उपयोग हो, तो प्रतापगढ़ जिले की अनुसूचित जनजातियाँ न केवल अपने समाज का उत्थान कर सकती हैं बल्कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति को भी नई दिशा दे सकती हैं।

Conclusion : प्रतापगढ़ जिले में अनुसूचित जनजाति का राजनीतिक योगदान न केवल संख्यात्मक है, बल्कि यह क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। इस समुदाय ने आरक्षण के माध्यम से धरियावद और प्रतापगढ़ विधानसभा सीटों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, जिससे उन्हें राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। यह प्रतिनिधित्व उन्हें अपने समुदाय की विशिष्ट जरूरतों और मुद्दों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और भूमि अधिकारों को प्रभावी ढंग से उठाने में मदद करता है। हालांकि, राजनीतिक भागीदारी के बावजूद, यह समुदाय अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों में गरीबी, अशिक्षा, और बुनियादी सुविधाओं की कमी प्रमुख हैं। इस समुदाय के नेताओं को इन मुद्दों को हल करने के लिए नीति निर्माण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भविष्य में, अनुसूचित जनजाति का राजनीतिक योगदान और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे–जैसे यह समुदाय शिक्षित और जागरूक हो रहा है, इसकी राजनीतिक चेतना भी बढ़ रही है। विभिन्न राजनीतिक दल इस समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए नई रणनीतियाँ बना रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रतापगढ़ की राजनीति में उनका महत्व लगातार बढ़ रहा है। कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि प्रतापगढ़ में अनुसूचित जनजाति का राजनीतिक योगदान समुदाय के सशक्तिकरण और जिले के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और यह भविष्य में भी एक निर्णायक कारक बना रहेगा।

References :

1. जैन, प्रकाश चन्द्र (1991), जनजातीय आंदोलनों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण : राजस्थान के भीलों का अध्ययन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
2. मथुर, लक्ष्मण प्रसाद (2000), ब्रिटिश राज में भील आंदोलनों का इतिहास, पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर।
3. वशिष्ठ, विजय कुमार (1997), भगत आंदोलन : दक्षिणी राजस्थान के भीलों में सांस्कृतिक रूपान्तरण का अध्ययन, श्रुति पब्लिकेशन्स, जयपुर।
4. राम, पेमाराम (1986), राजस्थान में कृषक आंदोलन (1913–1947 ई.), पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
5. भारत सरकार, जनगणना निदेशालय (2011), जिला जनगणना पुस्तिका – प्रतापगढ़ (भाग क एवं ख), जनगणना संचालन निदेशालय, राजस्थान।